P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-2* May- 2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में कृषि उपज की बिक्री एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): एक अध्ययन

Sale and Minimum Support Price of Agricultural Produce in India (MSP) A Study

Paper Submission: 03/05/2021, Date of Acceptance: 14/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021

नीलू कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
श0 दु 0 म0 राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोईवाला, देहरादून,
उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

कृषि उपज की कीमतों में उतार–चढ़ाव के अर्थव्यवस्था पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जहां एक ओर कृषि उत्पाद की कीमत में ज्यादा गिरावट आने से उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे अधिक उत्पादन करने के लिए हतोत्साहित होते हैं वहीं दूसरी ओर कृषि उपज की कीमत अधिक बढ़ने से उपभोक्ताओं पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं और उसे अपने अन्य खर्चो में कटौती करनी पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जिसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) हो गया। अपनी स्थापना के समय से ही यह आयोग उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के हितो को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करता रहा है। लेकिन इस शोध में यह देखा गया हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होनेवाले किसानों का प्रतिशत बहुत कम होने के साथ–साथ विभिन्न राज्यों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा अनाज खरीद के मामले में काफी विभिन्नताएँ हैं। ऐसे में कृषि मूल्य नीति को ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पाद एवं कृषि पदार्थ उत्पादक राज्य आ सकें।

Fluctuations in the prices of agricultural produce have many bad effects on the economy. Where on the one hand, due to fall in the price of agricultural produce, the producers are adversely affected and they are discouraged to produce more, on the other hand, due to the high rise in the price of agricultural produce, there are bad effects on the consumers and they have to spend in their other expenses. have to be cut. Keeping this in mind, the government established the Agricultural Prices Commission in 1965, which was renamed as the Commission for Agricultural Costs and Prices in 1985. Since its inception, this commission has been announcing the Minimum Support Price keeping in mind the interests of both the producer and the consumer. But it has been seen in this research that with the percentage of farmers benefiting from MSP is very low, as well as in different states, there is a lot of variation in the matter of procurement of food grains by the government at MSP. In such a situation, there is a need to strengthen the agricultural price policy so that more and more agricultural products and agricultural commodities producing states can come under the ambit of minimum support price.

मुख्य शब्द : न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि मूल्य नीति, कृषि मूल्य आयोग, कृषि उत्पाद।

Minimum Support Price, Agricultural Price Policy, Agricultural Price Commission, Agricultural Products

प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र के उत्पादन में विनियोग बढ़ाने एवं उत्पादकों को प्रोत्साहित करने में उस उत्पाद के मूल्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ तक कृषि उत्पाद के मूल्य का प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही मूल्य उच्चावचन को देखते हुए उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के दृष्टिकोण से कृषि पदार्थों के उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। क्योंकि कई बार अनाज ज्यादा पैदा हो जाने की वजह से किसानों को उसका दाम बहुत कम मिलता था, तो कई बार अनाज कम पैदा होने पर अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती थी। इसके समाधान के लिए 1 अगस्त,

1964 में नियुक्त एल. के. झा. कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1965 में हुई । इसका नाम 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) हो गया । इस आयोग का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि वस्तुओं के मूल्य गिरने की स्थिति से बचने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी प्रदान करना तथा उपभोक्ता के स्तर पर उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना हैं ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण एवं किसानों पर उसके पड़ने वाले प्रभावों के संबन्ध में काफी शोध हुए हैं। इनमें अधिकांश शोध न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि का कृषि एवं किसानों पर अच्छे प्रभाव को दर्शाते हैं। देव एवं नूथलपति (2010) ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि कृषि मूल्य नीति का किसानों को चावल एवं गेहूँ की लागत पर लगभग 20 प्रतिशत से अधिक लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। त्रिपाठी (2012) ने भी बताया है कि कृषि मूल्य नीति धान एवं गेहूँ की उत्पादन लागत पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में सफल रहा है जिससे कृषि में विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। वही अली (2012) ने अपने शोध में पाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति वैसे राज्यों में काफी प्रभावपूर्ण रहा है जहाँ धान का अतिरिक्त उत्पादन होता है। लेकिन उन राज्यों में ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं रहा है जहाँ धान की पूर्ति या उत्पादन उसकी माँग से कम है। यादव एवं ढाकुर (2018) ने भी यही बात कही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण नीति है एवं कृषकों की मूल्य उच्चावचन से सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्य तय करती है, से कृषक अधिक उत्पादन करने एवं कृषि में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ शोध में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को किसानो के लिए ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं बताया गया है। सिंह (2002) ने अपने शोध में कई कृषि उत्पादन पर अध्ययन में पाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कृषकों को कृषि उत्पादन के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं कर पाई । आदित्य, प्रवीण एवं शर्मा (2017) ने अपने निष्कर्ष में बताया है कि भारत में 75 प्रतिशत परिवार विभिन्न फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबन्ध में अनभिज्ञ थे । न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केवल धान एवं गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ही किसान जिज्ञासु थे वह भी केवल पंजाब, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में जहाँ से अनाजों की अधिक सरकारी खरीद बफर स्टॉक के लिए PDS के माध्यम से की जाती है।

इन विभिन्न शोध अध्ययनों की पृष्ठभूमि में इस शोध का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्यसे वास्तव में लाभान्वित होनेवाले किसानों, राज्यों एवं कृषि उत्पादों को इंगित करना है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य है :

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रवृतियों का अध्ययन करना,
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य का विभिन्न राज्य के किसानों को मिलने वाले लाभों को देखना तथा
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से की गई विभिन्न फसलों की खरीद की भिन्नता को इंगित करना ।

शोध विधि

यह शोध द्वितीयक समंक पर आधारित है। समंको का संकलन नीति आयोग की रिपोर्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रकाशन विभिन्न शोध पत्रों एवं इन्टरनेट से किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रवृतियों को जानने के लिए 2000–01 से 2020 तक के समकों को लिया गया है। जबकि अन्य विश्लेषण के लिए मुख्यत: 2014–15 से 2020–21 तक के समंको का उपयोग किया गया है। समंको के विश्लेषण के लिए औसत एवं प्रतिशत विधि प्रयोग में लाई गई हैं।

परिणाम एवं विश्लेषण

कृषि उपज बिक्री के क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का काफी महत्वपूर्ण स्थान है । न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों की बिक्री करनेवाले किसानों की निगाह प्रतिवर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा तय की जानेवाली विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अवश्य होती है। इस शोध में हमने वर्ष 2000–01 से 2020–21 तक की खरीफ एवं रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रवृतियों का अध्ययन किया है। हमने तीन भागों में 2000–01 से 2006–07 तक की औसत वृद्धि दर, 2007–08 से 2013–14 तक की औसत वृद्धि दर एवं 2014–15 से 2020–21 तक की औसत वृद्धि दर को देखने की कोशिश की है।

खरीफ फसलों में 2006–07 की तुलना में 2013–14 में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई है । इसमें सबसे अधिक औसत प्रतिशत वृद्धि क्रमश: मूँग (134.4), उड़द (129.2), अरहर (114.7), मडुआ (112.3), मूंगफली (110.4), सोयाबीन (105. 2) तथा ज्वार हाइब्रिड (102.9) में हुई है जबकि सबसे कम वृद्धि क्रमश: कपास (50.6), मक्का (88.2), बाजरा (88.8) तथा धान (84) की रही है। जबकि 2013–14 से 2020–21 के बीच मडुआ (117. 1) को छोड़कर सभी खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में औसतन कम प्रतिशत वृद्धि हुई है । हालांकि यह 2000–01 से 2006–07 बीच हुई औसत वृद्धि से अधिक है। (तालिका –1)

रबी फसलों में 2000–01 से 2006–07 तथा 2007–08 से 2013–14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में औसत वृद्धि की तुलना में 2014–15 से 2020–21 के बीच की न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि दर अधिक रही है। इसमें सबसे अधिक वृद्धि जूट (131.4), चना (105. 5), कुसुम (118) तथा तोर (101.8) में हुई है और सबसे कम वृद्धि क्रमश: गेहूँ (57.3),मसूर (85.9), सरसों (88.8) तथा जौ (98.5) में हुई है ।

तालिका : 1
खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 2000–01 से 2020–21 तक प्रतिशत वृद्धि

	2000–01 से 2006–07 तक		2007–08 से 2013–14 तक		2014–15 से 2020–21तक	
खरीफ फसल	औसत MSP	MSP में प्रतिशत वृद्धि	औसत MSP	MSP में प्रतिशत वृद्धि	औसत MSP	MSP में प्रतिशत वृद्धि
धान	550	7.8	1012	84	1612	59.2
ज्वार (हाइब्रिड)	537	-	1090	102.9	2004	83.8
बाजरा	501	12.5	946	88.8	1626	71.8
मक्का	504	13.2	949	88.2	1534	61.6
मडुआ	501	12.5	1064	112.3	2310	117.1
अरहर	1344	12	2886	114.7	5279	82.9
मूंग	1383	14.2	3221	134.9	5924	83.9
उड़द	1383	15.2	3170	129.2	5239	65.2
क्पास (मध्यम रेशा)	1716	5.6	2771	61.4	4479	61.6
कपास(लंबा रेशा)	1921	5.2	2894	50.6	4779	65.1
मूंगफली	1254	2.7	2636	110.2	4565	73.1
सोयाबीन (काले)	1308	11.7	2641	101.9	3315	25.5
सोयाबीन (पीले)	846	9.1	1736	105.2	2954	70.1

स्रोत : Formers' Portal, 8 January,2021 और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सितम्बर 2014 के आंकड़ों के आधार पर परिकलित

तालिका : 2
रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 2001 – 01 से 20 – 21 तक प्रतिशत वृद्धि

	2000–01 से 2006–07 तक		2007–08 से 2013–14 तक		2014–15 से 2020–21तक	
खरीफ फसल	औसत MSP	MSP में प्रतिशत वृद्धि	औसत MSP	MSP में प्रतिशत वृद्धि	औसत MSP	MSP में प्रतिशत वृद्धि
गेहूं	623	7.4	1095	75.7	1725	57.3
जौ	507	17.9	696	37.2	1382	98.5
चना	1257	23.8	2062	64	4239	105.5
मसूर	1419	18.2	2232	57.2	4150	85.9
सरसों	1422	22.2	2075	45.9	3918	88.8
कुसुम	1360	23.6	1942	42.7	4234	118
तोर	1387	30.2	1848	33.2	3731	101.8
जूट	836	11.4	1461	74.7	3382	131.4

स्रोत : Formers' Portal के आंकड़ों के आधार पर परिकलित

खरीफ एवं रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु इस मूल्य पर बहुत कम फसलों का क्रय सरकार द्वारा किया जाता है। अधिकाश फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बाजार में बिकी होती है । (तालिका 3) मे 2018–19 के दौरान गेहूं, चना एवं सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में वर्ष में कितने प्रतिशत दिनों में बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिकी हुई है उसे दिखाया गया है । इसमें गेहूं की औसतन 34.5 दिनों में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम थे। सबसे कम हरियाणा में 12.3 प्रतिशत दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार मूल्य कम थे जबकि सबसे अधिक उत्तरप्रदेश में 56.4 प्रतिशत दिनों में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम थे।

चना की 83.7 प्रतिशत दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बाजार में बिकी हुई है। चना के प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान की 100 प्रतिशत बिक्री बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र की 95.1 प्रतिशत जबकि कर्नाटक की 65.2 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश की 58.6 प्रतिशत दिनों में बिक्री बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर की गई है । सरसों की स्थिति इस मामले में और भी खराब रही है। क्योंकि इसकी औसतन 95 प्रतिशत बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर की गई है। राज्यवार देखने पर छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की 100 प्रतिशत बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर हुई है जबकि प० बंगाल एवं हरियाणा में क्रमश : 87.8 एवं 76.6 प्रतिशत दिनों में सरसों की बिक्री बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर हुई हैं ।

तालिका : 3

गेहूं, चना एवं सरसों के विभिन्न उत्पादक राज्यों में 2019–20 में बाजार मूल्य (MSP से कम मूल्य पर बिक्री)

गेहूं		चना		सरसों	
राज्य	दिन % जब बाजार मूल्य MSP से कम थे	राज्य	दिन % जब बाजार मूल्य MSP से कम थे	राज्य	दिन % जब बाजार मूल्य MSP से कम थे
हरियाणा	12.3	कर्नाटक	65.2	छत्तीसगढ़	100.0
मध्य प्रदेश	27.7	मध्य प्रदेश	100.0	गुजरात	100.0
राजस्थान	41.6	महाराष्ट्र	95.1	मध्य प्रदेश	100.0
उत्तर प्रदेश	56.4	राजस्थान	100.0	राजस्थान	100.0
		उत्तर प्रदेश	58.6	उत्तर प्रदेश	100.0
				पश्चिम बंगाल	87.8
				हरियाणा	76.6

स्रोत : AGMARKET

2018–19 में चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल खरीद प्रमुख चना उत्पादक राज्यों के कुल उत्पादन का केवल 9.8 प्रतिशत हुई है। इन राज्यों में तेलांगना के कुल उत्पादन का 25.8 प्रतिशत, गुजरात का 8.3 प्रतिशत, मध्यप्रदेश का 2.5 प्रतिशत तथा राजस्थान के कुल चना उत्पादन का केवल 0.3 प्रतिशत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद की गई है ।

इसी तरह सरसों की खरीद भी 2018–19 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों के उत्पादन का मात्र 13 प्रतिशत ही हुई । जिसमें सबसे कम उत्तर प्रदेश के कुल सरसों उत्पादन का मात्र 0.1 प्रतिशत ही क्रय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर । अन्य राज्यों में गुजरात (9.3 प्रतिशत), राजस्थान (14.2 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (16.5 प्रतिशत) तथा हरियाणा से (24.9 प्रतिशत) क्रय की गई। (तालिका : 4)

तालिका : 4

2018 –19 में राज्यवार चना एवं सरसों की खरीद RMS में

राज्य	चना की खरीद	उत्पादन के प्रतिशत में	राज्य	सरानो की खरीद	उत्पादन के प्रतिशत में
मध्य प्रदेश	5.8	12.5	राजस्थान	5.6	14.2
राजस्थान	1.0	0.3	हरियाणा	2.5	24.9
तेलंगाना	0.3	25.8	मध्य प्रदेश	1.8	16.5
महाराष्ट्र	0.2	2.3	गुजरात	0.3	9.3
गुजरात	0.2	8.3	उत्तर प्रदेश	0.01	0.1
कुल उत्पादन का प्रतिशत		9.8			13

स्रोत : NAFED के आंकड़ों के आधार पर परिकलित

खरीद के मामले में गेहूँ एवं धान का क्रय अध्ययन अवधि में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है क्योंकि इसका वितरण ही PDS के माध्यम से अधिकतम किया जाता है । किन्तु गेहूँ एवं धान की खरीद में 2014–15 से 2021 के बीच काफी उतार–चढ़ाव के साथ कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। गेहूं की खरीद 2014–15 में 35.83 लाख मिलियन टन से उतार – चढाव के साथ 2020–21 में 38.66 लाख मिलियन टन हुआ तो धान की खरीद 2014–15 में 3.75 लाख मिलियन टन से 2019–20 में 7. 36 लाख मिलियन टन। यानि धान की खरीद लगभग दोगुनी हुई। तालिका (5)

तालिका : 5

भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा 2014 –15 से विभिन्न वर्षो में धान एवं गेहूं का क्रय

गेहूं		धान	
श्रबी (RMS)	क्रय की मात्रा (LMT) में	खरीफ (KMS)	क्रय की मात्रा (LMT) में
2014-15	35.33	2014-15	3.75
2015-16	29.84	2015-16	9.62
2016-17	30.47	2016-17	11.86
2017-18	36.09	2017-18	7.75
2018-19	42.59	2018-19	6.74
2019-20	40.37	2019-20	7.36
2020-21	38.66	2020-21	-

स्रोत : Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, September,2020

गेहूं एवं धान की खरीद को जब हम राज्यवार देखें तो इसमें काफी असमानता दिखती है। 2009–10 से 2018–19 के बीच गेहूँ की मौसत खरीद कुल उत्पादन का 31.4 प्रतिशत हुई है। इसमें भी उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों से उनके उत्पादन के अनुपात में क्रमश: पंजाब से 68.8 प्रतिशत, हरियाणा से 64.7 प्रतिशत, एवं मध्यप्रदेश से 47.1 प्रतिशत की गई है। जबकि राजस्थान से उसके कुल उत्पादन का 14.9 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश से 9.2 प्रतिशत एवं बिहार से मात्र 3.4 प्रतिशत ही की गई है। जो गेहूँ की विभिन्न राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की असमानता को प्रदर्शित करता हैं। (तालिका : 6)

तालिका : 6

भारत के विभिन्न गेहूं उत्पादक राज्यों से की गई कुल खरीद एवं प्रतिशत के रूप में खरीद(2009–10 से 2018–19 तक)

	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		कुल
राज्य	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	खरीद मि० टन०	खरीद उत्पादन के प्रतिशत में	का प्रतिशत में
पंजाब	10.21	67.30	10.96	66.53	12.83	74.27	10.90	65.68	11.64	66.07	10.34	68.73	10.65	66.24	11.71	71.20	12.69	71.18	12.91	72.62	68.8
हरियाणा	6.35	60.45	6.93	59.57	8.67	68.31	5.87	52.83	6.50	55.04	6.78	65.46	6.75	59.48	7.43	64.36	8.78	81.60	9.32	79.97	64.7
मध्य प्रदेश	3.54	42.07	4.97	65.10	8.49	73.61	6.36	48.39	7.09	54.83	7.31	42.73	3.99	22.57	6.73	37.49	7.31	45.96	6.73	38.76	47.1
राजस्थान	0.48	6.34	1.30	18.06	1.96	21.07	1.27	13.67	2.16	24.92	1.30	13.23	0.76	7.72	1.25	13.86	1.53	16.35	1.40	14.57	14.9
उत्तर प्रदेश	1.65	5.98	3.46	11.54	5.06	16.71	0.68	2.25	0.63	2.10	2.27	10.11	0.80	3.13	3.70	12.31	5.29	16.61	3.64	11.30	9.2
बिहार	0.18	4.01	0.56	13.59	6.77	16.34	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.29	0.00	0.05	3.4
भारत	22.51	27.86	28.34	32.62	38.15	40.21	25.09	26.83	28.02	29.24	28.09	32.46	22.96	24.88	30.83	31.29	35.80	35.84	34.06	33.65	31.4

श्रोत : DFPD एवं DES, MOA & FW के आंकड़ों के आधार पर परिकलित

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-2* May- 2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

तालिका : 7

धान एवं गेहूं के समर्थन मूल्य (MSP)से लाभान्वित होने वाले किसानों का प्रतिशत

		धान						गेहूं					
क.सं.	राज्य	2015-16 RMS	2016-17 RMS	2017-18 RMS	2018-19 RMS	2019-20 RMS	औसत (%)	2016-17 KMS	2017-18 KMS	2018-19 KMS	2019-20 KMS	2020-21 KMS	औसत (%)
1	आंध्रप्रदेश	3.8	7.5	6.9	6.0	5.4	5..92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2	तेलंगाना	7.3	15.1	14.9	15.2	16.0	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3	आसाम	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4	बिहार	3.8	3.9	2.3	2.2	2.3	2.9	0.0	0.0	0.1	0.01	0.02	0.02
5	चंडीगढ़	0.1	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.1	0.03	0.04	0.05	0.03	0.05
6	छत्तीसगढ़	15.2	18.4	14.0	16.2	14.8	15.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
7	गुजरात	0.004	0.01	0.01	0.04	0.04	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
8	हरियाणा	2.9	7.7	9.4	8.6	15.2	8.76	23.1	27.1	22.2	25.4	18.0	22.08
9	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.01	0.01	36.8	7.36
10	झारखण्ड	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.01	0.01	0.1	0.03	0.03	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07	0.01
12	कर्नाटक	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
13	केरल	2.2	1.7	1.9	1.8	1.8	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
14	मध्यप्रदेश	2.7	3.9	3.9	3.9	3.5	3.58	26.0	23.2	24.1	27.0	36.8	27.42
15	महाराष्ट्र	1.5	2.1	1.6	2.8	4.2	2.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
16	उड़ीसा	14.8	15.2	11.0	10.4	9.5	12.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
17	पंजाब	16.5	15.0	15.8	11.8	9.1	13.24	40.8	26.5	22.6	23.3	24.2	27.48
18	तमिलनाडु	11.6	1.0	5.7	5.1	4.9	5.66	8.1	25.1	26.9	21.1	15.3	19.3
19	उत्तरप्रदेश	5.9	6.0	6.8	7.1	5.7	6.3	8.1	25.1	26.9	21.1	15.3	19.3
20	उत्तराखंड	7.1	1.1	0.1	0.6	0.7	1.92	0.03	0.02	0.4	0.2	0.1	0.15
21	पश्चिम बंगाल	9.9	8.8	4.8	7.6	6.5	7.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

स्रोत : Pib . gov. in. /Press Release, PIB, Delhi

कुल मिलाकर धान एवं गेहूँ उत्पादन राज्यों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ बहुत कम राज्य के किसानों को मिलता है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों का प्रतिशत क्रमानुसार 2015–16 से 2020–21 में छत्तीसगढ़ (15.7), पंजाब (13. 2), तेलांगना (13.7), उड़ीसा (12.8), हरियाणा (8.7), उत्तराखण्ड (7.5) तलिनाडु (5.6), उत्तरप्रदेश तथा आंध्र प्रदेश (5.9) है एवं बाकी राज्यों का प्रतिशत 0 से 5 के बीच है। दूसरी ओर गेहूँ के MSP से लाभ प्राप्त करनेवाले किसानों के अधिक प्रतिशत वाले राज्यों में पंजाब (27.48), मध्यप्रदेश (27.42), हरियाणा (22.08) तमिलनाडु एवं उत्तरप्रदेश (19.3) है तथा हिमाचल प्रदेश (7.36), उत्तराखण्ड (0.15) एवं बिहार (0.02) इस मामले में काफी पीछे है। अन्य राज्यों की स्थिति न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से लाभ के मामले में नगण्य ही है। (तालिका : 7)यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभ प्राप्त करनेवाले विभिन्न फसलों एवं विभिन्न राज्य के किसानों में काफी असमानता है जिसे दूर करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

किसानों के दृष्टिकोण से विचार करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके फसल के मूल्य के उच्चावचन से सुरक्षा प्रदान करना रहा है । जिससे अधिक उत्पादन होने पर बाजार में गिरते हुए मूल्य का सामना उन्हें नहीं करना पड़े एवं वे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हो । इस अध्ययन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रकृतियों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न फसलों को मिलने वाले लाभो को देखने की कोशिश की गई है। इसमें पाया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रत्येक वर्ष विभिन्न फसलों के लिए की गयी हैं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य हुई है। लेकिन उस मूल्य पर बहुत कम फसलों की सरकारी खरीद की गई है। अधिकांश फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बाजार में बिकते हैं।

जिन फसलों का मुख्य रूप से क्रय किया गया हैं विभिन्न वर्षों में वे केवल धान एवं गेहूं ही है । धान एवं गेहूँ की अधिकतम खरीद भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलांगना एवं छत्तीसगढ़ जैसे कुछ प्रमुख राज्यों से ही की गई है। परिणामस्वरूप धान एवं गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की ज्यादा संख्या भी इन्हीं राज्यों से हैं। धान एवं गेहूँ के अन्य उत्पादन राज्यों में बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय एवं किसानों को उससे मिलने वाले लाभों के मामले में काफी पीछे है।

आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित की जाती है उसपर उसकी बिकी भी हो वास्तव में जिस तरह धान एवं गेहूं की होती है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद का कोटा विभिन्न उत्पादक राज्यों के लिए समान रूप से निर्धारित हो ताकि सभी फसलों के उत्पादक राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।

संदर्भ

1. . *Aditya K.S, Subash S. P, Praveen K.V, Nithyashree M.L, Bhuvana N. and Sharma Akriti (2017), " Awarness about Minimum Support Price and Impact on Diversification Decision of Farmers in India" Asia and Pacific Policy Studies, Vol-4,no-3, PP. 514-526*
2. *Dev Mahendra and Chandra S.R. Nuthalapati (2010), "Agricultural Price Policy, Farm Profitability and Food Security" Economic and Political Weekly, 45(26), PP. 174-182*
3. *FCI रिपोर्ट, जून 2019*
4. *Malamasuri Kadasiddappa, Prashant Panmar Malpe Sachin, Soumya B (2013), "A Historical Perspective of Minimum Support Price of Agricultural crops, researchget.net*
5. *Report of Ministry of consumer Affairs, Food and Public Distribution, Pib. gove. in / Press Releas, 9 September, 2020*
6. *NITI Aayog (2016), "Evaluation Report on Efficiency of minimum Support Prices (MSP) on Farmers"*
7. *Singh S.J. (2002), "Impact of Minimum Support Prices on the Agricultural Economy Madhya Pradesh" Project Work*
8. *Tripathi Ashutosh Kumar (2012), "Agricultural Price Policy, Output and Farm Profitability – Examining Linkages during Post Reform Period in India" Asian Journal of Agriculture and Development, Vol-10, NO. 1*
9. *Yadav Ajay & Thakur Shailija (2018), "Minimum Support Price to Farmers in India" Popular Khet, volume 6, Issue-2*
10. *Report of commission for Agricultural costs and Prices (2019).*
11. *Publication of Reserve Bank of India, Sep 15, 2014*